Dr Kumari Manju
H.O.D - ECONOMICS
R.N.C. Hajipur

Credit control by central Bank

Ques Discuss the credit control by central Bank.

Ans केन्द्रीय बैंक देश में साख नियंत्रण हेतु निम्न दो रीतियां अपनाती है।

A. Quantitative Control (मात्रात्मक नियंत्रण) : इस रीति के अन्तर्गत :

(1) बैंक दर नीति (Bank Rate Policy) : बैंक दर से बिलों की पुनर्कटौती होती है और ऋण दिया जाता है। जब कभी व्यापारिक बैंक अपने स्त्रोतों से धन नहीं जुटा पाता है और उसे रुपये की आवश्यकता होती है तो वह या तो केन्द्रीय बैंक से अपने ग्राहकों की पुनर्कटौती करा लेता है या अपने प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण ले लेता है। इस सेवा के बदले में केन्द्रीय बैंक ब्याज लेता है जो बैंक दर या कटौती दर कहलाती है।

यदि इस बैंक दर में वृद्धि हो जाती है तो व्यापारिक बैंक भी अपने ब्याज दर में भी वृद्धि कर देते हैं अथवा इसके विपरित बैंक दर के कम होने पर व्यापारिक बैंक भी अपने ब्याज की दर कम कर देते हैं बैंक दर में परिवर्तन के निम्न प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है -

(i) साख संकुचन या विस्तार → यदि केन्द्रीय बैंक को यह ज्ञात होता है कि देश में मुद्रा स्फीति है तो वह बैंक दर बढ़ा देता है जिससे केन्द्रीय बैंक से प्राप्त ऋण महंगा हो जाता है तथा व्यापारिक बैंक भी ब्याज दर बढ़ा देते हैं। जिससे व्यापारिक बैंक से व्यक्ति कम ऋण लेते हैं जिससे साख की मात्रा में कमी हो जाती है।

इसके विपरित मंदी की अवस्था में जब साख की मात्रा में वृद्धि करनी हो तो बैंक दर कम कर दी जाती है जिससे व्यापारिक बैंक भी ब्याज दर घटा देते हैं और ब्याज दर कम होने से लोग बैंक से अधिक ऋण लेने लगेंगे जिसका परिणाम यह होगा कि साख की मात्रा में वृद्धि हो जायगी।

(ii) मुद्रा स्तर में कमी या वृद्धि : साख संकुचन के कारण व्यापार एवं औद्योगिक कार्यों में शिथिलता आ जाती है तथा आय कम हो जाती है और मूल्य स्तर भी कम हो जाती है। साख प्रसार के कारण व्यापारियों और उद्योगपतियों को अधिक विनियोग करने का प्रोत्साहन मिलता है, उत्पत्ति के साधनों को अधिक रोजगार प्राप्त होता है जिसके कारण उनकी आय में वृद्धि होती है और मूल्य स्तर बढ़ने लगता है। अतः केन्द्रीय बैंक जब देखता है कि देश में व्यावसायिक उन्नति के लिए अधिक साख की आवश्यकता है तो वह बैंक दर में कमी करके साख वृद्धि देता है परन्तु मुद्रा स्फीति के कारण वह बैंक दर बढ़ाकर साख में कमी कर देता है।

(iii) विदेशी पूँजी का आवागमन : बैंक दर बढ़ जाने से ब्याज दर की अन्य दरें बढ़ जाती हैं जिससे आकर्षित होकर विदेशी पूँजी अल्पकालिन विनियोग के लिए हमारे यहाँ आने लगती है तथा यह दर कम हो जाने से हमारे देश के पूँजी विदेशों में अधिक ब्याज की आशा में जाने लगती है।

(iv) विदेशी विनिमय दरों पर प्रभाव: बैंक दर बढ़ने से बाहर की पूँजी देश में आने लगती है जिससे व्यापार शेष देश के अनुकूल हो जाता है फलस्वरूप विनिमय दर भी देश के अनुकूल हो जाती है। बैंक दर जिसके कारण ऊपर के परिणाम होते हैं।

बैंक दर परिवर्तन होने पर आर्थिक क्रियाओं पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है इस सम्बन्ध में दो मत हैं- पहला Hawtry का मत है कि "बैंक दर में वृद्धि होने से बैंकों द्वारा दिए जाने वाले अल्पकालिन ऋण पर ब्याज की दर बढ़ती है जिससे व्यापारियों का माल रखने का व्यय बढ़ता है क्योंकि रखे हुए माल में लगी हुई पूँजी पर ब्याज देना पड़ता है जब माल रखने का व्यय बढ़ता है तो व्यापारी कम माल अपने पास रखता है और निर्माण कर्ताओं को माल मंगाने का कम आदेश देता है जिसके कारण रोजगार और मौद्रिक आय में कमी होती है आय कम होने पर उपभोग

Scanned with CamScanner

में कमी आती है जिससे वस्तुओं के मूल्य घटते हैं। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है।"

* इसप्रकार — बैंक दर घटने से उपरोक्त क्रियाओं के विपरीत लक्षण उत्पन्न होते हैं।

(B) Qualitative credit Control by central Bank: विभिन्न उद्देश्यों के बीच साख का नियंत्रण करना ही गुणात्मक साख नियंत्रण कहलाता है। इसके निम्न लक्षण हैं:

(i) ये साख के आवश्यक और अनावश्यक उपयोगों में भेद करते हैं।

(ii) केवल अनावश्यक उपयोगों को ही बैंक नियंत्रणों के अन्तर्गत लाया जाता है,

(iii) ये न केवल ऋणदाता को प्रभावित करते हैं अपितु ऋणियों को भी प्रभावित करते हैं।

Methods:

(1) **साख की राशनिंग:** इस रीति के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक साख की अधिकतम सीमा निर्धारित कर देता है और उसमें से विभिन्न प्रकार की व्यवसायों के लिए एक कोटा निर्धारित कर दिया जाता है। किसी भी बैंक को उसके निर्धारित कोटा से अधिक साख उपयोग करने की आज्ञा नहीं होती। साख नियंत्रण का दूसरा तरीका परिवर्तनशील पूँजीगत सम्पत्ति अनुपात है जिसके अनुसार केन्द्रीय बैंक वह अनुपात निश्चित कर देता है जो किसी व्यापारिक बैंक की पूँजी और उसकी कुल सम्पत्ति में होना चाहिए। संक्षेप में साख की राशनिंग निम्न प्रकार से अपनाया है:

(i) किसी बैंक की पुनः भुगतान की सुविधा समाप्त करके, (ii) किसी बैंक की पूँजी और कुल सम्पत्ति में अनुपात निश्चित करके।

(iii) किसी बैंक की पुनः भुनाने की सीमा को सीमित करके।

(iv) विभिन्न बैंकों के लिए साख की कोटा निश्चित करके।

(2) **प्रतिभूति ऋणों की आवश्यकता सीमा में परिवर्तन:** इस रीति का प्रयोग उस साख के नियंत्रण के लिए किया जाता है जो सट्टा कार्यों के लिए किए जाते हैं। केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के सट्टे के कार्यों के लिए प्रतिभूतियों की जमानत पर दिए जाने वाले ऋण की सीमा निर्धारित करता है।

संक्षेप में, प्रतिभूतियों के मूल्य और उधार दी जाने वाली राशि के अंतर को Margin कहते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि 200 रु० की प्रतिभूति के जमानत पर 150 रु० ऋण दिया जा रहा है तो Margin 50 रु० होगा। इसे इस प्रकार से भी समझा जा सकता है मान लो बैंकों के ऋण देते समय 10% मार्जिन रखना है अर्थात 100 रु० के गेहूँ पर 90 रु० उधार दिया है। अब गेहूँ की बढ़ती हुई कीमत को रोकने के लिए अब बैंकों को यह आदेश देता है कि अमुक तिथि से Margin 50 प्रतिशत होना चाहिए तो बैंक अपने ग्राहकों से कहेंगे कि या तो 40 प्रतिशत गेहूँ या उतनी धनराशि जमा करायें ताकि 50 प्रतिशत हो जाए। इस तरह बैंकों के पास सिर्फ यही रास्ता होगा कि गेहूँ बेचकर नकद राशि बैंक में जमा कर दें। इस तरह बाजार में गेहूँ की पूर्ति बढ़ेगी और मूल्य घटेगा। बैंकों के पास साख मात्रा में कमी आ जाएगी। इस प्रकार Margin ऋण दाता को नियंत्रित करती है और ऋणों पर रोक लगाकर साख की मात्रा को कम कर देती है।

इसका प्रयोग केवल साख के विस्तार को सीमित करने के लिए ही किया जाता है उसके विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं।

(3) **उपभोक्ता की साख नियंत्रण:** इस रीति के अन्तर्गत उपभोक्ता द्वारा अनावश्यक मूल्यवान वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय को हतोत्साहित किया जाता है जिससे देश में जितनी अधिक टिकाऊ वस्तुओं का stock होगा उतनी ही शीघ्र व्यापार चक्रों से प्रभावित होती है अतः यहाँ मुद्रा प्रसार या मुद्रा संकुचन रोकने के लिए आवश्यक है कि उपभोक्ता द्वारा टिकाऊ वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय को संतुलित किया जाए।

Scanned with CamScanner

अतः मुद्रा स्फीति रोकने के लिए अधिक से अधिक वस्तुएँ जो किस्त के आधार पर बेची जाती हैं उन पर नियंत्रण लगा देना चाहिए, तथा उपभोक्ता ऋणों का भुगतान शीघ्रता से करें। जैसे एक सिलाई मशीन खरीदने के लिए उसका एक तिहाई मूल्य तुरंत चुकाना पड़ता है और शेष 20 प्रतिशत मासिक किस्तों पर तो इन उपभोक्ता ऋणों को नियमित करने वाले कानूनों तत्कालिक भुगतान की राशि को बढ़ा देना चाहिए। और किस्तों की संख्या को कम करना चाहिए। इसके विपरीत मुद्रा संकुचन को रोकने के लिए विपरीत रीति अपनाना चाहिए।

(4) नैतिक दबाव: केन्द्रीय बैंक नैतिक दबाव डालकर उनको अपनी नीति के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है यदि देश में मुद्रा स्फीति है तो केन्द्रीय बैंक अन्य व्यवसायिक बैंकों पर दबाव डालते हैं कि वे जनता को अधिक ऋण स्वीकृत न करें।

इसके विपरीत मंदी के समय केन्द्रीय बैंक अन्य बैंकों को उनके ऋणों की मात्रा में वृद्धि करने का आदेश दे सकता है।

(5) विज्ञापन तथा प्रचार की नीति: केन्द्रीय बैंक अपनी नीति को सफल बनाने के अनुकूल से विज्ञापन द्वारा जनता को यह बताने का प्रयास करते हैं कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हितों को देखते हुए साख सम्बन्धी कौन सी नीति अधिक उपयुक्त होगी एवं कौन-कौन बैंक नीति का पालन करते हैं। यह नीति बहुत कुछ नैतिक प्रभाव नीति का ही एक स्थानापन्न स्वरूप है।

(6) शेयर बाजार के ऋणों की सीमा में परिवर्तन: शेयर बाजार के ऋणों की सीमा में परिवर्तन साख नियंत्रण का यह तरीका भी अपेक्षाकृत नवीन है तथा इसका प्रयोग सबसे पहले अमेरिका में हुआ था। इस तरीके का प्रयोग प्रतिभूतियों में सट्टे के लिए उपयोग की जाने वाली साख की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। व्यवसायिक बैंक प्रायः प्रतिभूतियों के आधार पर सट्टे के लिए ऋण देते हैं। अतः केन्द्रीय बैंक इस प्रकार के नियम बना देता है कि सट्टेबाजी के लिए सीमित मात्रा में ही ऋण प्रदान किया जाए इसके लिए वह व्यवसायिक बैंकों द्वारा सट्टे के लिए दिए जाने वाले ऋणों की सीमा निर्धारित कर देता है।

※ दूसरा मत De Kock का है कि इसके अनुसार " बैंक दर में परिवर्तन होने से बाजार में किसी प्रकार के प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय में स्थिरता आ जायेगी।"

Objective of Credit Control: प्रो० रॉबर्टसन ने कहा कि "मुद्रा जो मानव जाति के लिए अनेक सुखों का स्रोत है, नियंत्रण के बिना संकट एवं उलझनों का कारण भी बन सकती है"। साख का नियंत्रण समय-समय पर परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होते रहता है। स्वर्णमान के पतन के पूर्व ऐसा सोचा जाता था कि मुद्रा प्रणाली में स्वयं संचालकता का गुण होने के कारण यदि विनिमय दरों में स्थिरता को कायम रखा जा सके तो मुद्रा के आंतरिक मूल्य अथवा कीमत स्तर में स्थिरता स्वयं ही आ जायेगी इसलिए साख नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य विनिमय-दरों में स्थिरता प्राप्त करना था। परन्तु 1930 की महान मंदी ने यह स्पष्ट कर दिया कि विनिमय-स्थिरता की अपेक्षा कीमत स्थिरता देश की आर्थिक हितों के लिए आवश्यक है इस विचारधारा के अनुसार साख नियंत्रण का उद्देश्य मुद्रा के आंतरिक स्थिरता की प्राप्ति समझा जाने लगा। आधुनिक विचारधारा के अनुसार विनिमय-स्थिरता तथा मूल्य स्थिरता दोनों ही आवश्यक हैं।

वर्तमान समय में केन्द्रीय बैंकों की साख-नियंत्रण नीति का उद्देश्य स्थिरता प्राप्त करने के साथ-साथ आर्थिक विकास में सहायक होना भी है। साख नियंत्रण के उद्देश्य वही होते हैं जो मौद्रिक नीति के उद्देश्य होते हैं। साधारणतया साख नियंत्रण अथवा मौद्रिक नीति के उद्देश्य निम्न हैं — (I) विनिमय दरों में स्थिरता, (II) आंतरिक मूल्यों अथवा कीमत स्तर की स्थिरता (III) आय एवं रोजगार की ऊँची दर पर स्थिरता (IV) आर्थिक विकास की गति में स्थिरता।